what is there to consider in view of the fact that the foreign exchange reserves are coming down after many years?...

MR. CHAIRMAN: Now your questions are becoming irrelevant.

SHRI J. VENGAL RAO: I have answered the question very clearly....

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: Not very clearly.

SHRI J. VENGAL RAO: BHEL which is coordinating on the Indian side has sought some clarifications. If you want to take cooperation from an outside NRI company, we have to form a separate company in India. We have not formed that...

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: That is their offer. It is part of the 51 per cent shareholdings and they will form a company. That is part of their proposal. What are you examining?

SHRI J. VENGAL RAO: We have asked for so many clarifications. They have not yet given them...

SHRI NIRMAL CHATTERJEE: Is it part of the proposal?

SHRI J. VENGAL RAO: It is under examination. We have not committed ourselves on anything.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chatterjee, please read the answer. It says "The proposed consultancy joint venture contemplates 51 per cent shareholding by the non-resident Indian firm." That is all he can answer and he has answered it.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Mr. Chairman, Sir, my worry is that the Minister may be technically correct when he says that a non-resident can hold more than 50 per cent of the shares. But a recent news item said that there is out-flow of capital from this country...

MR. CHAIRMAN: Not related. Next Question.

Rajghat Thermal Power Station

*82. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Thermal Power Station at Rajghat is not in operation for the last several months due to a dispute between the DESU and the Central Pollution Control Board; and

(b) if so, what are the details thereof and what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF POWER IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRIMATI SUSHILA ROHATGI): (a) and (b) To prevent pollution and to meet the requirements of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, the Delhi Electric Supply Undertaking is installing an electrostatic precipitator at the 15 MW Unit of the Rajghat Thermal Power Station. Meanwhile, pending the consent of the Central Board for Prevention and Control of Water Pollution, the Unit is not being operated on a commercial basis.

श्री शान्ति त्यागी : सर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि एयर पोल्यूशन को रोकने के लिये राजघाट थर्मल पावर स्टेशन में प्रेसीपिटेटर लगाया जा रहा है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस उपकरण को लगाने में कितना रुपया खर्च आयेगा और इसी में यह भी बताने की कृपा करें कि पिछले वर्षों में यह प्लांट कितनी बार खराब हुआ है और उसकी खराबी की मरम्मत में कितना रुपया जाया करना पड़ा ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, जैसे माननीय सदस्य ने पूछा है इसमें 9 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है और पिछले साल यह जो है यह 26 अप्रैल

को आउट आफ् सर्विस होने से रोक दिया था। इस बीच में इस बात का प्रयास किया गया कि इसको फिर से रेनोवेट किया जाये, रिवेम्प कराया जाये और जेनरेटर फिर से चालू हो जाये। यही देखते हुए कि अभी काम नहीं चल रहा है और डेसू और इसमें आपस में दो अलग-अलग रायें हैं, अभी निर्णय यही किया गया है कि यह प्रेसीपिटेटर लगाया जाये और यह आशा है कि अगली मई तक यह प्रेसीपिटेटर लगा दिया जायेगा।

श्री शान्ति त्यागी : मेरा सैकेण्ड सप्लीमेंट्री यह है कि एयर पोल्यूशन रोकने के लिये करोड़ों रुपया खर्च करने जा रहे हैं और जो इस प्लांट में बार-बार खराबी आती है उसकी मरम्मत पर भी करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं और इस पावर स्टेशन की उम्र जो विशेषज्ञ कहते हैं वह चार-पांच साल से ज्यादा नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब इतना रुपया इसके ऊपर खर्च आ रहा है तो क्या इस पावर स्टेशन को आप बन्द करने का विचार करेंगे ?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, यही देखत हुए कि यह 1966 में स्थापित हुआ था और काफी पुराना यह थर्मल पावर स्टेशन है और इस पर प्रेसीपिटेटर लगाने में काफी रुपया लगेगा, यही सोचकर आपस में दो राय थी, लेकिन कोई डिसप्यूट नहीं था पर जजमेंट यह था कि इस पर ज्यादा रुपया क्यों लगाया जाये जिस के लिये इसको रिव्यू किया गया और यह काम चालू करने के लिये परमिशन मांगी गई, परन्तु कन्ट्रोल बोर्ड ने इसको उचित नहीं समझा और यह इनसिस्ट किया कि यह प्रेसीपिटेटर लगाया जाये जिसके लिये आर्डर प्लेस किया गया है और 1 करोड़ 26 लाख रुपये उसको लगाने में खर्च होंगे। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार के और भी पोल्यूशन को रोकने के यहां प्रयास किये जा रहे हैं। यहां पर राजघाट थर्मल पावर स्टेशन जैसा आपने कहा कि इसको बंद किया जाये तो इसके लिये यह भी विचार किया जा रहा है कि 67.5 मेगावाट के दो और नये यूनिट यहां पर तैयार कर दिये जायें।

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI: Sir, this is not the only one kind of its type of thermal plants which is out of order. The West German experts who came to this country five years back have given a report which is still considered to be very confidential. Nearly 50 per cent of the thermal power stations which are installed in our country are out of order. And the Badarpur centre and also the station are not manned properly and thermal stations are not maned properly. In this context, would the Minister like to have a re-look into the whole things to what is the total installed capacity in thermal plants in this country how many of them are out of order at present and how many of them would be reinstalled? Secondly, what happened to the captive thermal plants? How many of them have been installed in the country?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Mr. Chairman, Sir, if the report is very confidential, I am surprised how the hon. Member got it. But all the same, about the points that she has brought out, many of these thermal power plants are working very well. On the whole we find that some of them need renovation and modernisation. And we have a scheme of about Rs. 500 crores which is looking into this matter, which will be completed within three years, And there are about 39 stations of power plants which should be undergoing this renovation and modernisation and which should be yielding the results. At the same time, the entire CEA and the Ministry is looking very deeply into all the thermal plants and trying to locate where the defects lie so that they can be brought to their fullest utilisation.

MR. CHAIRMAN: Yes, Shri Virendra Verma.

DR. (SHRIMATI) SAROJINI MAHISHI. Are there not many confidential things kept open on the Table of the House and not known to the Members?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, ...

MR. CHAIRMAN: Well, no personal explanation is required in this case. Yes, Mr. Virendra Verma.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि सन् 1981 ईसवी में प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था। उस वक्त से इस प्रदूषण को रोकने में प्रेसीपिटेटर कितने वर्ष बाद लगाया और कितने दिनों तक वह ठीक प्रकार से कार्य करता रहा ? या अब लगाने का उनका इरादा है ? अगर इसमें देरी हुई है तो उसका क्या कारण है?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : मान्यवर, 1981 में यह प्रदूषण रोकने के लिये जो नए मेजर्स दिये गये हैं, इनीशियेट किये गये हैं कि ज्यादा स्ट्रेथन उसी के आधार पर विचार किया गया कि यहां पर प्रेसीपिटेटर लगाया जायं और जैसा मैं पहले बता चुकी हूं, इसमे दो रायें थी, आवश्यकता है या नहीं है। पहले यह निर्णय हो गया कि नहीं प्रेसीपिटेटर लगाना आवश्यक है, इससे यह एश की कंटेण्ट कम होगी और हमारा स्मोक वगैरह कम होगा और प्रदूषण इससे रुकगा। इसलिये यह तय किया गया, 1985 में इसका निर्णय हुआ और 1986 में आर्डर प्लेस हो गये हैं फरवरी 1987 में यह काम पूरा हो जायेगा ?

SHRI N. K. P. SALVE: Sir, the answer of the Minister is very heartening that the Central Pollution Control Board is taking care to reduce the pollution caused by the coal ash that is given out by the Rajghat Power Station. Sir, I have lived in an area where I have known what tremendous devastation this power ash causes. Sir, May I tell the Hon. Minister that an expert from Japan told me that Tokyo has a thermal power station in the midst of the city and it has only a small white streak of smoke coming out of it. I was talking to one of the experts and I said, how come this happens when you use precipitators in power stations which use coal. He said that only a special quality of coal is allowed to be used in the thermal power stations where they are located within the city and if the high ash content coal is used even the ash precipitators are not able to take care of it. May I know from the Minister whether they would consider at least in the case of thermal power stations within cities to supply special quality of coal which has low ash content?

SHRIMATI SUSHILA ROHATGI: Sir, all these things are under the active consideration and examination of the Government, how to utilise this and how to reduce the pollution and the suggestions that he has offered we will look into them in detail and the Government is very much aware of it.

श्री सुरेश पचौरी : माननीय सभापति महोदय, अभी जैसा कि मंत्री जी ने बताया कि यह प्लांट 1966 में स्थापित हुआ था और बारंबार इस थर्मल प्लांट, राजघाट मे खराबी आयी। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीच में भी डेसू ने अपने रेजोल्यूशन 769 के माध्यम से इस प्लांट को ठीक कराने का ठेका मेसर्स लेंदोहम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दिया था और अब इस इलेक्ट्रो-स्टेटिक प्रेसीपिटेटर लगाने का ठेका "भेल" को दिया है। मान्यवर, बोर्ड ने डेसू को 3.5 मेगावाट लोड पर जो अभी तक चलाने की अनुमति दी है, जिससे डेसू को काफी आर्थिक हानि उठानी पडेगी। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि प्रदूषण को मद्देनजर रखते हुए जनहित में, इस प्लांट को होने वाली आर्थिक हानि को भी मद्देनजर

रखते हुए जहां इस प्लाट को बंद कर देना उचित है, वहीं थर्मल पावर स्टेशन की ऐसी कितनी स्कीम है जो सेण्ट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास अभी तक लंबित पड़ी हैं ? इनका निपटारा कब तक हो जायेगा और उनका विवरण क्या है ?

MR. CHAIRMAN: Now this question relates to DESU and you are asking information about all the other power stations. Now the Minister will reply to the first part of the question.

श्रीमती सुशीला रोहतगी : श्रीमन्, माननीय सदस्य ने अपने प्रश्न के पहले हिस्से में कहा है कि 3.5 मेगावाट की डेसू को अनुमति दी गई है। अभी हाल में इसको मेक्सिमम लेवल पर 15 मेगावाट की अनुमति दी गई है जिसके लिए 12 दिसम्बर की सीमा दी गई है। उन्होंने एक दिन चलाया है, चेक किया है, उसको इन्सपेक्ट किया है कि उसकी इस समय स्थिति क्या है और उस के बाद बन्द कर दिया है।

Oil Struck in Maharashtra and Gujarat coasts

*83. SHRI MURLIDHAR CHANDRAKANT BHANDARE:†

SHRI MAHENDRA PRASAD:

Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ONGC have struck a major oil find in the western offshore belt of Maharashtra and Gujarat coasts;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what steps have been taken and are being taken by Government for further explorations in and around the area and for exploitation of these resources to their best use?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI BRAHM DUTT): (a) to (c) Oil was struck by ONGC at the following three locations recently in the Western offshore areas:—

Name of the well	Location	Date
CD-1	50 Km. South East of South Tapti Gas Field (about 75 km. West of Daman)	May, 1986
CA-1	Do.	Sept., 1986
B-42-1	150 km. West from Bombay	Sept., 1986

Further exploratory drilling is planned to be taken up to assess the potential of these finds. The exploitation of these resources will be undertaken on the basis of the results of further exploratory drilling and assessment of the resources in the area.

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri Murlidhar Chandrakant Bhandare.